मुख्यमंत्री डॉ. यादव 'राज्य डेटा के लिए सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने' पर कार्यशाला का किया शुभारंभ

सीमाओं की सुरक्षा की तरह महत्वपूर्ण है डेटा की सुरक्षा : मोहन

सच प्रतिनिधि ॥ भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आज की सबसे मूल्यवान संपत्ति डेटा है। डिजिटल सुरक्षा समय की मांग है। डेटा की सुरक्षा, राष्ट्र की सीमा की सुरक्षा जितनी महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ वर्षों में न केवल देश अपितु पूरी दुनिया में सायबर तकनीक और उससे जुड़ी चुनौतियों का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। हर दिन इसके नए आयाम सामने आ रहे हैं। अपराध के तरीके भी लगातार बदल रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आधुनिक तकनीक और ड्रोन जैसे साधनों के उपयोग से सुरक्षा चुनौतियों का नया स्वरूप देखने को मिला। प्रधानमंत्री श्री मोदी का देश की सुरक्षा को हर तरह से सशक्त बनाने के लिए अभिनंदन है। प्रधानमंत्री श्री मोदी की विशेषता है कि वह समय से पहले आने वाले वाली चुनौतियों को पहचान लेते हैं और शासन-प्रशासन और जन सामान्य को उसके प्रति जागरूक करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम भी उठाते हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी के निर्देश पर सायबर अपराध, डीप फेक और अन्य चुनौतियों पर केंद्रित कार्यशाला में सायबर सुरक्षा संस्कृति को सशक्त बनाने में सभी मार्ग खोजे जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राज्य डेटा के लिए सायबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को सुदृढ़ बनाने पर सोमवार को कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दीप प्रज्जवलित कर कार्यशाला का शुभारंभ किया। कार्यशाला का उद्देश्य राज्य शासन

के विभिन्न विभागों में सायबर सुरक्षा से जुड़ी वर्तमान चुनौतियों, उभरते सायबर खतरों, डेटा संरक्षण की आवश्यकताओं और डिजिटल शासन प्रणालियों की सुरक्षा पर व्यापक विचार-विमर्श करना है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सायबर अपराध और डेटा सुरक्षा की दिशा में ठोस कदम उठाते हुए राज्य में सायबर सिक्योरिटी रिसर्च सेंटर स्थापित करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मधु स्थित मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से यह रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा। सेंटर केंद्रीय सायबर सुरक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास के लिये महत्वपूर्ण आधार बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सायबर अटैक की समय पर पहचान और निगरानी में आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था से लैस सेंटर की महती भूमिका होगी। यह व्यवस्था केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि पूर्वानुमान आधारित निरंतर सतर्कता की दिशा में ठोस कदम साबित होगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा है कि मध्यप्रदेश बदलते दौर में हर तरह की चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। सायबर अपराधियों के विरुद्ध मध्यप्रदेश पुलिस ने अच्छा काम करके दिखाया है। वर्ष 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने जीरो बैलेंस पर बैंक अकाउंट खोलने की शुरुआत की। जनधन खाते खुलने से देशभर में जरूरतमंदों को डीबीटी के माध्यम से हितलाभ सीधे उनके बैंक खाते में दिया जाने लगा। डीबीटी की पारदर्शी व्यवस्था लागू होने से शत प्रतिशत लाभ हितग्राहियों तक पहुंचने लगा। दुनिया ने भारत की यूपीआई पेमेंट सिस्टम का लोहा माना है। ऐसे समय में जब नागरिकों को डिजिटल और ऑनलाइन माध्यम से लाभ पहुंच रहा है तो सरकार पर सुरक्षा की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। नागरिकों के मन में विश्वास पैदा करने के लिए राज्य सरकार हर पहलू को ध्यान में रखकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सुरक्षा के तमाम चाक-चौबंद उपायों के बाद भी अगर जीवनभर की गाढ़ी कमाई एक झटके में कोई सायबर अपराधी उड़ा ले जाए तो दुःख होता है। सायबर क्राइम के अदृश्य खतरों से निपटने के लिये सभी आवश्यक प्रबंधन करना वर्तमान दौर की जरूरत है। सायबर क्राइम और डेटा सेफ्टी के मामले में लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं है। राज्य का डेटा हमारी सबसे मूल्यवान संपत्ति है। डेटा ब्रीच की स्थिति में आर्थिक भरपाई की जिम्मेदारी भी सरकार की होगी। प्रदेश सरकार सायबर सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। प्रमुख सचिव, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एम. सेल्वेन्दन ने कहा कि मध्यप्रदेश ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है। विभाग नागरिकों को डिजिटल और ऑनलाइन सेवाएँ उपलब्ध कराने के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की विभिन्न डिजिटल नवाचारों को राष्ट्रीय स्तर पर सराहना और पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ सायबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण की चुनौतियाँ भी बढ़ी हैं, इसलिए नागरिकों के व्यक्तिगत, वित्तीय, भूमि, शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी डेटा की सुरक्षा राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रमुख सचिव सेल्वेन्दन ने कहा कि इसी उद्देश्य से एमपी-सीईआरटी की स्थापना की गई है, जो सायबर खतरों की निगरानी, त्वरित प्रतिक्रिया और समन्वित कार्रवाई से प्रदेश की सायबर सुरक्षा को सुदृढ़ कर रहा है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार के मार्गदर्शन में आयोजित यह कार्यशाला सायबर सुरक्षा के लिए मजबूत संस्थागत एवं नीतिगत ढाँचा विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। कार्यशाला में प्राप्त सुझावों के आधार पर प्रदेश में सुरक्षित, विश्वसनीय एवं भविष्य उन्मुख साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क को और मजबूत किया जाएगा। प्रबंध संचालक एमपीएसईडीसी आशीष वशिष्ठ ने कहा कि प्रदेश में 1700 से अधिक शासकीय सेवाएं डिजिटली नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ सायबर सुरक्षा और डेटा संरक्षण का महत्व भी बढ़ा है। नागरिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि एवं संपत्ति सहित विभिन्न शासकीय अभिलेखों की सुरक्षा सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। एमडी श्री वशिष्ठ ने बताया कि प्रदेश में एमपी-सीईआरटी, स्टेट डेटा सेंटर के सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर और सुरक्षित स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (स्वान) से सायबर सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ किया जा रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कार्यशाला में प्राप्त सुझावों और विशेषज्ञों के अनुभवों के आधार पर राज्य के लिए एक मजबूत, प्रभावी और भविष्य उन्मुख साइबर सुरक्षा फ्रेमवर्क विकसित करने में सहायता मिलेगी।

सभी समाजों को, उनकी परम्पराओं को जोड़ें, आल्हा-ऊदल स्मृति उत्सव और श्रावण महोत्सव भी मनायें

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि आगामी छह-सात माह में बड़े त्यौहार, सांस्कृतिक पर्व एवं मेले मनाये जायेंगे। ये सभी त्यौहार हमारी धार्मिक आस्थाओं और प्रकृति के प्रति हमारी कृतज्ञता के प्रतीक हैं। इन सभी अवसरों पर संस्कृति विभाग सभी समाजों को, उनकी आस्थाओं और सांस्कृतिक परम्पराओं को जोड़कर वृहद आयोजन करें। आल्हा-ऊदल वीर रस गायन के प्रतीक हैं, उनकी स्मृति में आयोजन किए जाएं। श्रावण महोत्सव और भुजरिया पर्व भी मनाएं। नागपंचमी पर जैव विविधता संरक्षण (सर्प प्रजातियों के संरक्षण) का संदेश दिया जाये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि संस्कृति विभाग लोगों को जोड़कर ऐसे आयोजन करें, जिनसे हमारी कला और संस्कृति के संवर्धन के साथ ही सरकार के संदेश का भी प्रसार हो। मुख्यमंत्री सोमवार को मंत्रालय में संस्कृति विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं एवं गतिविधियों की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश की कला, संस्कृति, परम्पराएं और समृद्ध पुरातात्विक धरोहरें प्रदेश की अमूल्य पूंजी हैं, जिन्हें संरक्षित और संवर्धित करना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने के लिए योजनाबद्ध और प्रभावी प्रयास किए जाएं। डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के सांस्कृतिक

अभ्युदय के लिए हमारी सरकार हर जरूरी प्रयास कर रही है। हम समाज को साथ लेकर इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। बैठक में संस्कृति, पर्यटन एवं धार्मिक न्यास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री धर्मेन्द्र सिंह लोधी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने संस्कृति विभाग द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए तैयार किये गये %कला पंचांग% का विमोचन भी किया। इसमें विभाग द्वारा वर्ष भर की जाने वाली कलात्मक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का पूरा कैलेंडर तैयार किया गया है। अब इन्हें सिलसिलेवार क्रियान्वित किया जायेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि भविष्य में प्रदेश में धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का दायरा और तेजी से बढ़ेगा। विभागीय आंतरिक विशेषताओं और विशेषज्ञताओं का समुचित संयोजन करते हुए संस्कृति विभाग की और बेहतर पुनर्संरचना की जाये। विभागीय गतिविधियों का आधुनिक संदर्भों में विस्तार भी किया जाये। उन्होंने कहा कि संस्कृति, पर्यटन, धार्मिक न्यास और कुटीर एवं ग्रामोद्योग विभाग सभी मिलकर काम करें, ताकि प्रदेश में धार्मिक एवं आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिले। इससे प्रदेश में उत्कृष्ट कारीगरी से निर्मित होने वाले क्रॉफ्ट आइटम्स, हैंडलूम आइटम्स और कशीदाकारी को भी पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सम्राट वीर विक्रमादित्य के नाम से एक पुरुष अकादमी का गठन किया जाये। इसमें विक्रमादित्य के जीवनवृत्त पर समग्र शोध एवं अन्य संगत गतिविधियां भी संचालित की जायें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य के बाहर के प्रसिद्ध मंदिरों और देव स्थानों के अतिरिक्त अब प्रदेश में मौजूद 2 ज्योतिर्लिंगों, जागृत एवं मंशापूर्ण शक्ति पीठों एवं अन्य धार्मिक स्थलों को भी मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना में शामिल किया जाये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने विशेष रुप से श्रीराम वन गमन पथ और श्रीकृष्ण पाथेय परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को इनके निर्माण कार्यों में और अधिक गति लाने के निर्देश दिए।

मध्य प्रदेश में महिला बाल विकास मंत्री की चेतावनी

महिलाओं पर कॉमेडी पड़ेगी भारी

सच संवाददाता ॥ इंदौर

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और कॉमेडी शोज में महिलाओं का मजाक उड़ाना अब भारी पड़ेगा। ऐसे मामलों में अब सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये कहना है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी का। केंद्रीय मंत्री ने ये बात सोमवार को इंदौर में आयोजित महिला-बाल विकास विभाग की एक समीक्षा बैठक के दौरान कहीं।उन्होंने आगे कहा कि लैंगिक आधार पर महिलाओं से भेदभाव या उनके कामकाज के तरीकों का मजाक बनाना भी अब अपराध की श्रेणी में शामिल होगा। दरअसल, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने कहा है कि देश के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के अलावा विभिन्न प्रसार मध्यमों पर महिलाओं के काम काज के तरीकों के अलावा उनकी ड्राइविंग आदि पर कॉमेडी मीम्स और वीडियो बनते हैं जो कहीं न कहीं महिलाओं के साथ असमानता और उन्हें कमतर आंकने का प्रयास है। ऐसे में ऐसी रील्स बनाने पर भी दंड का प्रावधान किया जा रहा है। इंदौर में महिला एवं बाल विकास योजनाओं की दो

जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा,महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी या कॉमेडी करने वालों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है।इस दौरान उन्होंने बालिकाओं की शादी की उम्र और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे विषयों पर पूछे गए सवालों के जवाब में मंत्री ने कहा, ऐसे संवेदनशील विषयों को लेकर सरकार के स्तर पर नहीं बल्कि समाज में जागरूकता बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे युवा सही दिशा में आगे बढ़ सकें।इंदौर केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी सोमवार गोमटगिरि स्थित महिला एवं बाल विकास विभाग के संस्थान पहुंचीं थीं। इस दौरान उन्होंने विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और महिला एवं बाल कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी। मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, %% महिला एवं बाल विकास संस्थान देशभर में महिला एवं बाल विकास से जुड़ी योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। यहां मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया जाता है, जो आगे देश के लगभग 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों तक प्रशिक्षण और योजनाओं की जानकारी पहुंचाते हैं।उन्होंने बताया कि मिशन वात्सल्य और मिशन शक्ति जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत भी यहां प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिससे योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।

उद्घाटन से पहले पुल धंसा ॥ 1100 करोड़ रुपए की लागत से बना था, बाहर निकलने लगा सरिया

सच संवाददाता ॥ खंडवा

खंडवा-खरगोन सीमा पर निर्माणाधीन इंदौर-इच्छापुर फोरलेन परियोजना में गंभीर निर्माण खामी सामने आई है। करीब 3900 करोड़ रुपये की इस परियोजना के तहत बासवा नदी पर बन रहे लगभग 1100 करोड़ रुपये लागत वाले पुल का एक हिस्सा यातायात शुरू होने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया। पुल के स्लैब में गड्ढा बन गया है और उसमें इस्तेमाल किए गए लोहे के सरिए बाहर दिखाई देने लगे हैं।ग्रामीणों ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया है। उनका आरोप है कि पुल पर केवल चार इंच मोटा स्लैब डाला गया है और 10 एमएम के सरियों की दोहरी लेयर का उपयोग किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि इस पुल से भारी वाहनों का आवागमन शुरू हुआ तो बड़ा हादसा हो सकता है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, क्षति सामने आने के बाद निर्माण कंपनी ने जल्दबाजी में दोनों ओर बैरिकेडिंग कर दी और टूटे हिस्से

को तिरपाल से ढक दिया। ग्रामीणों ने आशंका जताई है कि निर्माण में हुई खामियों को छिपाने की कोशिश हो रही है। उन्होंने पूरे मामले की स्वतंत्र तकनीकी जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है।इंदौर-इच्छापुर नेशनल फोरलेन परियोजना खंडवा, खरगोन और बुरहानपुर जिलों से होकर गुजर रही है। ऐसे में परियोजना की गुणवत्ता पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जब पुल अभी शुरू भी नहीं हुआ और उसकी यह हालत है, तो भविष्य में इसकी मजबूती और सुरक्षा को लेकर चिंता होना स्वाभाविक है।मामले पर हड्डा के खंडवा प्रभारी आशीष बिरला ने कहा कि इसे पूल धंसने की घटना नहीं कहा जा सकता, बल्कि यह निर्माण संबंधी तकनीकी समस्या है। उन्होंने बताया कि इंजीनियरों की टीम से जांच कराई जा रही है और तकनीकी रिपोर्ट तैयार की जा रही है। रिपोर्ट मिलने के बाद संबंधित ठेकेदार को नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक इंतजाम कर दिए गए हैं और सुधार कार्यों की संभावनाओं का आकलन किया जा रहा है। इस संबंध में निर्माण कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर रूद्र हजारे ने बताया कि पुल अभी निर्माणाधीन है और इसे किसी भी प्रकार के यातायात के लिए अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद कुछ भारी वाहन, जिनमें सरियों से भरे ट्रक भी शामिल थे, पुल पर चढ़ गए। उन्होंने बताया कि भारी सरियों का पुल के जॉइंट में फंस जाने के कारण एक ओर का हिस्सा प्रभावित हुआ, जिससे सीमेंट का कुछ भाग धंस गया। कंपनी का दावा है कि पुल पूरी तरह सुरक्षित है और किसी प्रकार का कोई संरचनात्मक खतरा नहीं है। प्रभावित हिस्से की मरम्मत कर दी जाएगी। एहतियात के तौर पर सभी मार्गों पर बैरिकेडिंग कर भारी वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है। इंदौर-खंडवा-इच्छापुर-एदलाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण कार्य जारी है। लगभग 202 किलोमीटर लंबी यह सड़क मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण क्षेत्रों को जोड़ने वाली एक प्रमुख परियोजना मानी जा रही है।परियोजना के तहत सैकड़ों पुल-पुलियाओं और बड़े ब्रिजों का निर्माण किया जा रहा है। करीब पांच वर्षों से निर्माण कार्य चल रहा है।

मोरटक्का के सिक्स लेन पुल को लेकर बढ़ी चिंता

ओंकारेश्वर से लगभग 12 किलोमीटर दूर मोरटक्का में नर्मदा नदी पर करीब सवा किलोमीटर लंबा छह लेन पुल भी इसी परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो लगभग बनकर तैयार हो चुका है। बासवा पुल की स्लैब धंसने की घटना के बाद लोगों के मन में अन्य पुलों और संरचनाओं की गुणवत्ता को लेकर भी आशंकाएं बढ़ गई हैं। परियोजना अधूरी होने के कारण ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को अभी भी पुराने मार्ग का उपयोग करना पड़ रहा है। विशेष अवसरों और धार्मिक पर्वों के दौरान इस मार्ग पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग जाता है, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि यातायात शुरू होने से पहले ही पुल की स्लैब में इस तरह की समस्या सामने आ रही है, तो परियोजना के सभी पुलों, पुलियाओं और सड़क निर्माण कार्यों की स्वतंत्र तकनीकी जांच कराई जानी चाहिए। भविष्य में किसी भी संभावित दुर्घटना को रोकने के लिए गुणवत्ता परीक्षण और निगरानी को सर्वोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है।

जॉब के लिए बंगलूरू गए ग्लोबल स्किल पार्क के 34 छात्र लौटे वापस

सच प्रतिनिधि ॥ भोपाल

भोपाल स्थित ग्लोबल स्किल पार्क (जीएसपी) के प्लेसमेंट प्रबंधन पर सवाल खड़े हो गए हैं। संस्थान के 34 छात्रों को नौकरी दिलाने के लिए बंगलूरू भेजा गया था, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उन्हें बताया गया कि जिस पद के लिए भर्ती होनी थी, उसकी वैकेंसी फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इसके बाद छात्रों को बिना जॉइनिंग के वापस भोपाल लौटना पड़ा। अब उनको ग्लोबल स्किल पार्क के हॉस्टल में रखा गया है। जानकारी के अनुसार, ग्लोबल स्किल पार्क के 34 छात्र-छात्राओं का चयन बंगलूरू की स्नाइडर इलेक्ट्रिक कंपनी में हुआ था। इनकी ज्वाइनिंग 8 जून को होनी थी। इसके लिए पांच जून को बच्चे अपने-अपने साधनों से बंगलूरू 7 जून को पहुंचे। इसका मैनेजमेंट प्लेसमेंट एजेंसी विजन इंडिया द्वारा किया जा रहा है। हालांकि, कंपनी पहुंचने पर छात्रों को बताया गया कि संबंधित पदों की वैकेंसी भर चुकी है और फिलहाल भर्ती नहीं की जा सकती। बताया जा रहा है कि विजन इंडिया ने छात्रों को इसके बाद चेन्नई स्थित श्नाइडर इलेक्ट्रिक की मैन्युफैक्चरिंग में कंपनी में नौकरी का विकल्प दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया। वहीं, कुछ छात्रों को दूसरी कंपनी में प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) का प्रस्ताव भी दिया गया, जिसे भी उन्होंने अस्वीकार कर दिया। स्थिति स्पष्ट नहीं होने और जॉइनिंग नहीं मिलने के कारण सभी छात्र 11 जून को वापस भोपाल लौट आए। इस दौरान रहने, खाने और यात्रा सहित अन्य खर्च छात्रों को स्वयं वहन करना पड़ा। छात्रों के अनुसार, प्रत्येक छात्र को लगभग 10 से 12 हजार रुपये तक का खर्च उठाना पड़ा।

इस पूरी प्रक्रिया में ग्लोबल स्किल पार्क और कंपनियों के बीच विजन इंडिया नाम की प्लेसमेंट एजेंसी काम कर रही थी। ऐसे में सवाल उठ रहे है कि सीधे कंपनियों से अनुबंध करने वाले ग्लोबल स्किल पार्क को प्लेसमेंट एजेंसी की आखिर आवश्यकता क्यों पड़ी?

रतलाम पुलिस ने तैयार किया सिलेबस

स्कूल-कॉलेज में पढ़कर बच्चे होंगे समझदार

सच संवाददाता ॥ रतलाम

पुलिस द्वारा स्कूल एवं कॉलेज के छात्र-छात्राओं में अपराधों के प्रति जागरूकता लाने के लिए विशेष पाठ्यक्रम तैयार किए गए हैं। स्कूल और कॉलेज में अब सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध और नशे की रोकथाम जैसे विषय पढ़ाए जाएंगे। रतलाम पुलिस ने इन विषयों पर पाठ्यक्रम भी तैयार किया है। जिनके माध्यम से युवाओं को यातायात नियमों का पालन करना, नशे से दूर रहना और साइबर अपराधों से बचाना सिखाया जाएगा। रतलाम पुलिस ने इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी लीड कॉलेज और आंगनवाड़ी एवं आशा उषा कार्यकर्ताओं को इस अभियान से जोड़ा है।रतलाम पुलिस द्वारा युवाओं को वर्तमान में हो रहे अपराधों के प्रति जागरूक करने के तहत विभिन्न विषयों पर विशेष

पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। जिसमें साइबर अपराध, यातायात नियम एवं सड़क सुरक्षा, नशे से बचाव और महिला एवं नाबालिगों के विरुद्ध होने वाले अपराध की रोकथाम विषयों को स्कूल कॉलेज के छात्र-छात्राओं को पढ़ाया जाएगा।रतलाम एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया कि विशेष अधिकारी लीड कॉलेज और महिला बाल विकास विभाग को पत्र लिखा गया है जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्र-छात्राओं और आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता के माध्यम से महिलाओं एवं युवतियों को अपराधों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए रतलाम पुलिस ने 4 विषयों पर डिजिटल बुक एवं पाठ्य पुस्तक तैयार किया है। एडिशनल एसपी विवेक कुमार शुरुआत की गई है। इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी लीड कॉलेज और महिला बाल विकास विभाग को पत्र लिखा गया है जिसमें स्कूल कॉलेज के छात्र-छात्राओं और आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता के माध्यम से महिलाओं एवं युवतियों को अपराधों के प्रति जागरूक किया जाएगा। इसके लिए रतलाम पुलिस ने 4 विषयों पर डिजिटल बुक एवं पाठ्य पुस्तक तैयार किया है। एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया कि अक्सर देखा जाता है की सड़क दुर्घटनाओं में सर्वाधिक मौतें युवाओं की होती है। नशे की लत के शिकार सबसे अधिक युवा ही होते हैं।

वहीं, सोशल मीडिया का अधिक इस्तेमाल करने की वजह से साइबर फ्रॉड के शिकार भी अधिकांश युवा ही होते हैं। युवाओं में इन विषयों पर जागरूकता लाने के लिए स्कूल एवं कॉलेज के छात्र-छात्राओं को अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। जिससे महिला अपराधों, साइबर अपराध, नशे संबंधी अपराध और यातायात सुरक्षा के बारे में समाज में जागरूकता आ सकेगी।बहरहाल रतलाम पुलिस द्वारा तैयार किए गए पाठ्यक्रम को शुरुआत में रतलाम जिले में शिक्षा विभाग एवं लीड कॉलेज द्वारा छात्रों को पढ़ाया जाएगा। इसके बाद रतलाम पुलिस को इस पहल को अन्य जिलों में भी अपनाया जाएगा।

पूर्व मंत्री के बेटे से रंगदारी, खदान चलाने के एवज में 3 लाख की डिमांड

सच संवाददाता ॥ रतलाम

आलोट और ताल क्षेत्र में गिट्टी खदान और विभिन्न प्रोजेक्ट में अड़ंगे लगाकर वसूली करने का मामला सामने आया है। प्रदेश के पूर्व राज्यमंत्री मनोहर ऊंटवाल के बेटे मनोज बंटी ऊंटवाल से गिट्टी खदान का काम चलने देने की एवज में 3 लाख रुपये की मांग की गई है।

पीड़ित मनोज ऊंटवाल ने ताल थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। इसमें कहा गया नागदा निवासी अशोक गुर्जर द्वारा खदान का काम नहीं होने देने और विरोध प्रदर्शन कर बदले में रुपयों की मांग की जा रही है। शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है अशोक गुर्जर नाम का व्यक्ति विदेशी मोबाइल नंबर से फोन कर लगातार रुपयों की मांग कर रहा है। ऐसा नहीं करने पर ग्रामीणों को एकत्रित कर खदान पर भूख हड़ताल और काम नहीं होने देने की धमकी दे रहा है। ताल थाना क्षेत्र के माल्या गांव में गिट्टी खदान का विरोध स्थानीय ग्रामीण और कुछ लोग कर रहे थे। विरोध प्रदर्शन को बंद करवाने और खदान चलने देने की एवज में खदान मालिक से रुपयों की मांग की गई शिकायतकर्ता मनोज उर्फ बंटी ऊंटवाल भाजपा नेता और पूर्व राज्य मंत्री मनोहर ऊंटवाल के पुत्र हैं। मनोज ऊंटवाल ने बताया अलसी गांव का रहने वाला अशोक गुर्जर खुद को भारतीय किसान यूनियन मंच का प्रदेश उपाध्यक्ष बताता है और खदान के विरोध में ग्रामीणों को भड़काकर भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन कर रहा था। इसके बाद वह खदान का विरोध नहीं करने के बदले में 3 लाख रुपए के रिश्वत की मांग की जा रही है। उसके द्वारा विदेश के नंबर से फोन कर रुपये की मांग की जा रही है और ऐसा नहीं करने पर खदान नहीं चलने देने की धमकी दी जा रही है। शिकायतकर्ता ने आरोपी द्वारा की जा रही रुपयों की मांग और पूर्व में भी ईंट-भट्टों का विरोध प्रदर्शन कर 15 लाख रुपए वसूलने से संबंधित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी शिकायत पत्र के साथ दी है।